भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1653
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

तिरुपति में उद्योग 4.0 और युवा कौशल विकास

1653. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उभरती प्रौद्योगिकियों में उच्च-स्तरीय कौशल विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कोई उद्योग 4.0-केंद्रित कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ख) क्या तिरुपति में किसी संस्थान - जैसे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), एसवी विश्वविद्यालय या कौशल विकास केंद्रों का उद्योग 4.0 प्रतिभा विकास या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण पहलों हेतु चयन किया गया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को तिरुपति जैसे जिलों में युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने हेतु समर्थन या प्रोत्साहन दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन्हें पहलों के अंतर्गत शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या तिरुपति के युवाओं को राष्ट्रीय उद्योग 4.0 और डिजिटल विनिर्माण अवसरों से लाभान्वित करने के लिए लक्षित सहायता दी जाएगी?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के अंतर्गत 2.79 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नामांकित किया है । यह कार्यक्रम उद्योग संघ नैसकॉम के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को एआई, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, साइबर सुरक्षा आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाना है।

सरकार ने हाल ही में तिरुपति में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) का एक केंद्र स्थापित किया है। नाइलिट तिरुपति वर्तमान में एआई, आईओटी, डेटा इंजीनियरिंग, 3डी प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, पायथन प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एम्बेडेड सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कार्यक्रम प्रदान करता है।

तिरुपति में एसटीपीआई केंद्र स्थानीय आईटी/आईटीईएस उद्योग और स्टार्टअप/उद्यमियों को वैधानिक सेवाएं, इनक्यूबेशन सेवाएं, हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन (एचएसडीसी) सेवाएं, भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) आदि सेवाएं प्रदान कर रहा है।

पिछले 11 वर्षों में, सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को विकसित करने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल उत्पादन 28 गुना बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू की है। यह योजना प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरक, मुद्रित सर्किट बोर्ड, उप-असेंबली, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल आदि जैसे घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देती है। यह योजना आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के आवेदकों के लिए खुली है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में चार (4) ईएमसी स्थापित किए हैं:

i. गाँव- चेरिवी , सत्यवेदु मंडल, चित्तूर जिला
ii. विक्रुतमाला गाँव, येरपाडु मंडल, चित्तूर जिला
iii. रेनिगुंटा और येरपाडु मंडल, चित्तूर जिला, हवाई अड्डे के पास, तिरुपति
iv. कोप्पर्थी , कडप्पा, वाईएसआर जिला

लगभग 62 कंपनियों ने लगभग 6,421 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे 59,694 अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की संभावना है।

सरकार ने 2021 में विशाखापत्तनम में उद्योग 4.0 पर कल्पतरु उद्यमिता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है। अब तक, कल्पतरु सीओई ने 45 स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की है।

****